Statement

(a) Yes, Sir. The target for addition to capacity during 1990-91 was 4212 MW; this consisted of 967 MW by Central Sector Corporations and 3245 MW by State Electricity Boards and other utilities. Against the target of 967 MW, the Central Corporation added 732 MW to their capacity. The State Electricity Boards and other Utilities added 2044.5 MW against their target of 3245 MW.

(b) the main reasons for shortfall were slow progress of civil and unit erection works, delay in equipment supplies, inadequate cash flow and project inputs and disturbed law and order conditions in some States.

(c) The projects which have slipped from 1990-91 programme have been included in the commissioning programme for 1991-92 except for Suratgarh Hydroelectric Project (Unit No. 1 to 2) and Pampore GT Stage-II (Unit No. 3 & 4). The State Governments have been advised to take suitable steps so that these projects are commissioned in 1991-92.

Problem of Air taxi Operators

*195. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether the Air Taxi scheme is facing trouble as the operators are running into huge losses because they are not permitted to import spare parts;

(b) if so, whether there are any demands from these air taxi operators to operate on external sectors also to fetch them foreign exchange required to import spares; and

(c) il so, what is the Government's reaction thereto, particularly in view of liberalised trade policy of Government?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND ' TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) No, Sir.

(b) and (c). It is not possible to permit private air taxi operators to operate on external sectors.

एच. बी. जे. पाइपलाइन से गैस लेने के लिये लम्बित आवेदन-पत्र

*196. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच बी जे पाइपलाईन से गैस खरीदने के लिये मंत्रालय के पास कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं ;

(ख) आवेदकों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने अपने आवेदन कब भेजे थे ;

(ग) इन आवेदन पत्रों को अब तक स्वीकृति दिये जाने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन आवेदन पत्रों पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के पास लगभग 294 आवेदन पत्र लंबित हैं। एच० बी० जे० पाइपलाइन से प्राप्त होने वाली संपूर्ण गैस की स्थिति की समीक्षा की जा रही है ।

उ. प्र. राज्य विद्युत बोर्ड का कामकाज

*197. डा. रत्नाकर पाण्डेय : क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत बोर्ड को लगातार घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए वर्षवार घाटे का ब्यौरा क्या है तथा इस घाटे के क्या कारण हैं ;

(ग) भारत सरकार को उ० प्र० विद्युत बोर्ड द्वारा आज की तारीख तक कितनी धनराशि का भुगतान करना है ; और

(घ) उ० प्र० विद्युत बोर्ड के कार्य-कारण में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की हानियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता शामिल नहीं है :

31 मार्च को समाप्त वर्ष	निवल घाटा (करोड़ रुपए में)
1988 . .	383.90
1989 . .	438.20
1990 . .	470.50

उक्त हानियों के कारणों में ये शामिल है—विद्युत की औसत बिक्री दर उपभोक्ताओं को ऊर्जा पहुंचाने तक की लागत से काफी कम होना, ताप-विद्युत एवं जल-विद्युत उत्पादन क्षमता का मिश्रण उपयुक्त न होना और पारेषण एवं वितरण हानियों की प्रतिशतता का अत्यधिक होना ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भुगतान की जाने वाली राशि 31-7-91 की स्थिति के अनुसार लगभग 650 करोड़ रुपए बैठती है ।

(घ) राज्य बिजली बोर्ड राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकाय है । भारत सरकार द्वारा उ०प्र०रा०बि० बोर्ड सहित सभी बिजली बोर्डों के कामकाज में सुधार किए जाने का प्रयास किया जाता रहा है । वार्षिक योजना संबंधी विचार-विमर्श के अलावा, इस मामले पर समय-समय पर विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार-विमर्श किया जाता है । राज्य सरकारों को निम्नलिखित जैसे उपाय किए जाने की सलाह दी गई थी—ऋण को इक्विटी के रूप में परिवर्तित करना, कृषि क्षेत्र को विद्युत सप्लाई किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियों की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना, टैरिफ की आवधिक रूप से पुनरीक्षा किया जाना, हानियों को कम करने की दृष्टि से पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार करना आदि । भारत सरकार द्वारा विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 में संशोधन करके निवल परिसम्पत्तियों पर 3% का न्यूनतम सांविधिक अधिशेष प्राप्त किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है और विद्युत की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है ।

कांटी ताप विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता

*198. **श्री रजनी रंजन साहू** : क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरपुर स्थित कांटी ताप विद्युत स्टेशन की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) वहां उत्पादित विद्युत का वितरण किस प्रकार किया जाता है ; और